भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-1474
उत्तर देने की तारीख-09.02.2026

बाराबंकी जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात

†1474. **श्री तनुज पुनिया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पीएम-श्री योजना के तहत विकास के लिए बाराबंकी जिले में चयनित विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा बीच में छोड़ देने की उच्च दर की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बाराबंकी के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) यूडाइज+ 2024-25 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात क्रमशः 20 और 15 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 21 और 44 है। केंद्र सरकार, समय-समय पर संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में, **पीएम श्री योजना** के तहत **25 पीएम श्री** स्कूलों का चयन किया गया है।

(ग) केंद्र प्रायोजित योजना '**समग्र शिक्षा**' के फोकस क्षेत्रों में से एक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। स्कूल छोड़ने की दर के मुद्दे का समाधान करने के लिए, स्कूल अवसंरचना में सुधार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की स्थापना, कक्षा 8 तक नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक/वर्दी प्रदान करने

सहित विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। इसी तरह, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत, एक केंद्र प्रायोजित योजना, कक्षा 8 तक सभी छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है।

स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की पहचान की जाती है और उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु वर्ग के ओओएससी को मुक्त विद्यालय के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन तक पहुंचने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, बाराबंकी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट की समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं:

i. अधिगम परिणामों में सुधार के लिए माध्यमिक विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
ii. कक्षा 6 से 8 तक के लिए **15 केजीबीवी टाइप-III** और **3 केजीबीवी टाइप-IV** स्कूल कार्यात्मक हैं, और लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुंच, प्रतिधारण और निरंतरता में सुधार के लिए सभी 15 टाइप-III केजीबीवी को **कक्षा XII तक उन्नत** किया गया है।
iii. **मुख्यमंत्री मॉडल समग्र विद्यालय योजना** के तहत जिले में दो समग्र विद्यालय (प्राथमिक से कक्षा 12 तक) स्थापित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय भूकंपरोधी भवनों, स्मार्ट कक्षाओं, उन्नत विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, बहुउद्देशीय हॉल, बच्चों के अनुकूल शौचालयों, स्वच्छ पेयजल और रैंप से सुसज्जित हैं। एक ही स्थान पर प्री-प्राइमरी से कक्षा XII तक शिक्षा प्रदान करने से निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करके ड्रॉपआउट को कम करने में सहायता मिलती है।
iv. गुणवत्ता, पहुंच और प्रतिधारण में सुधार के लिए डिजिटल पहल सहित परियोजना अलंकार (एक राज्य पहल) और समग्र शिक्षा के माध्यम से अवसंरचना और अधिगम सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।
v. **परियोजना अलंकार** के तहत, 1,436.77 लाख रुपए की कुल लागत से 2 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं, 2 स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, 6 स्कूलों में बहुउद्देशीय हॉल, 3 स्कूलों में पुस्तकालय, 7 स्कूलों में बाउंड्री वॉल और 3 स्कूलों में विद्युतीकरण का काम पूरा किया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया है कि बाराबंकी में कुल 792 सरकारी स्कूलों (कक्षा VI और उससे ऊपर) को स्मार्ट क्लासरूम से सुसज्जित किया गया है और सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है।

****